



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2017/अग्रहायण 8, 1939

No. 449]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2017/AGRAHAYANA 8, 1939

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### अधिसूचना

मुंबई, 21 नवम्बर, 2017

**सं. टीएएमपी/65/2017-सीएचपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा चेन्नई पत्तन न्यास द्वारा 17 सितंबर, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/22/2016- सीएचपीटी के द्वारा वर्तमान अनुमोदित दरमानों के आशोधन के रूप में कार्गो प्रहस्तन परिचालनों के लिए आधी-पाली गैंग सिस्टम को पुनः लागू करने के प्रस्ताव का संलग्न आदेश के अनुसार निपटान करता है।

### महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### मामला संख्या. टीएएमपी/65/2017-सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास

---

आवेदक

### गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

### आदेश

(नवंबर, 2017 के 14वें दिन को पारित)

यह मामला चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के 17 सितंबर, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/22/2016-सीएचपीटी द्वारा अनुमोदित उनके वर्तमान दरमानों के आशोधन के रूप में कार्गो प्रहस्तन परचालनों के लिए आधी-पाली गैंग को पुनःबहाल करने के सीएचपीटी के 28 जुलाई, 2017 के प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. वर्ष 2014 में, सीएचपीटी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्गो प्रहस्तन कार्य और पर्यवेक्षी स्टॉफ की आपूर्ति के प्रभावों से संबंधित दरमानों में इस प्रभाव की टिप्पणी शामिल करने का प्रस्ताव किया है कि स्टीवडोर को आने वाले और कार्य पूरा हो चुके पोतों के लिए स्थायी आधार पर पूर्णकालीन पाली के स्थान पर आधी-पाली के लिए गैंग की मांग करने और

वर्तमान मज़दूरी के 50% का भुगतान करके 50% मज़दूरी पर 192% उगाही करने की अनुमति दी जायेगी। उक्त टिप्पणी इस आधार पर तब पत्तन द्वारा लागू करने का प्रस्ताव था कि स्टीवडोर आंशिक पाली कार्य के लिए गैंग के तैनात करने के अनिच्छुक होते हैं क्योंकि उन्हें पूरे गैंग प्रभार देने पड़ते हैं और कि आधी-पाली प्रभारों के निर्धारण से स्टीवडोर आधी पाली के लिए श्रम की मांग कर सकेंगे और इस प्रकार अधिक पोतों के प्रहस्तन के कारण उन्हें अतिरिक्त आय भी होगी। जैसा कि 28 नवंबर, 2014 के आदेश के पैरा 12 (xiv) में दर्ज है, तब सीएचपीटी ने सूचित किया था कि आधी-पाली गैंग व्यवस्था को मान्यताप्राप्त ट्रड यूनियनों और स्टीवडोर एसोसिएशन के साथ परामर्श से लागू किया गया है और परिणामस्वरूप शिप-दिवस उत्पादन में वृद्धि, निष्क्रिय घंटों में और पोतों के टर्न अराउंड समय में कमी आई है। दीर्घ काल में, इससे अधिक पोतों के प्रहस्तन से अतिरिक्त आय होगी। तदनुसार, इस प्राधिकरण ने 28 नवंबर, 2014 के अपने आदेश संख्या टीएएमपी/19/2014-सीएचपीटी के द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, सीएचपीटी द्वारा तब प्रस्तावित टिप्पणी को लागू करने का अनुमोदन किया गया।

2.2. तथापि, बाद में, सीएचपीटी ने अपने दरमानों के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव में, सीएचपीटी ने बताया कि सितंबर, 2015 में एनआईटी अवार्ड के कार्यान्वित होने पर, श्रम लागत में लगभग 16% तक घटौती हुई है स्टीवडोर श्रम प्रभारों और सामान्य उगाही को बरकरार रखते हुए, सीएचपीटी ने आधी-पाली गैंग प्रभारों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया था। आधी-पाली गैंग प्रभारों को समाप्त करने पर प्रयोक्ताओं ने भी कोई आपत्ति नहीं की थी। इस प्राधिकरण ने 17 सितंबर, 2016 के अपने आदेश संख्या टीएएमपी/22/2016-सीएचपीटी में, सीएचपीटी द्वारा दरमानों के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव का निपटान करते समय आधी-पाली गैंग प्रभारों को समाप्त करने का अनुमोदन किया।

3.1. इस पृष्ठभूमि में, सीएचपीटी ने 28 जुलाई 2017 के अपने पत्र संख्या ए.ओ (दरमान)/10611/2015/एफआर के द्वारा स्टीवडोरों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर आधी-पाली गैंग सिस्टम को पुनः लागू करने का प्रस्ताव दायर किया। सीएचपीटी द्वारा उठाये गए मुख्य मुद्दों का सारांश इस प्रकार है:-

- (i). सीएचपीटी के दरमान समय-दर मज़दूरी और 'प्रति पाली' आधार पर कार्गो प्रहस्तन के लिए श्रम की तैनाती के लिए 192% सामान्य लेवी का निर्धारण करते हैं। स्टीवडोरों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, अप्रैल 2013 में आने वाले पोतों के लिए आधी-पाली गैंग प्रभार लागू किये गए थे और बाद में बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करके जून, 2013 में इन्हें फिनिशिंग पोतों के लिए भी लागू कर दिया गया। तदनुसार, स्टीवडोरों को आने वाले पोतों के आगमन पर और कार्य समाप्त हुए पोतों के नौवहन की समय-दर मज़दूरी और उगाही के 50% के भुगतान पर आधी-पाली गैंग तैनात करने की अनुमति दी गई थी। इस संबंध में, आवश्यक उपबंध राजपत्र संख्या 358 दिनांक 10.12.2014 द्वारा अधिसूचित 28.11.014 के प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/19/2014-सीएचपीटी के द्वारा दरमानों के अध्याय - VII - मान -1- स्टीवडोर परिचालन की टिप्पणी संख्या 2 (ख) में शामिल किया गया था।
- (ii). 2016 के दौरान दरमानों में सामान्य संशोधन के समय, एनआईटी अवार्ड के कार्यान्वयन के कारण मानव शक्ति में अत्यधिक घटौती और पाली की शेष अवधि में आधी-पाली के लिए तैनात कामगारों के न्यून उपयोग से पत्तन को हुई राजस्व हानि को देखते हुए आधी-पाली गैंग प्रभार व्यवस्था को छोड़ दिया गया। दरमानों के संशोधन के लिए सीएचपीटी का प्रस्ताव न्यास की वेबसाइट पर है और प्राधिकरण द्वारा इस मामले में 21.07.2016 को संयुक्त सुनवाई भी की गई थी। तत्पश्चात्, प्राधिकरण ने अपने 17.09.2016 के आदेश संख्या: टीएएमपी/22/2016-सीएचपीटी के द्वारा सीएचपीटी के दरमानों का संशोधन अनुमोदित किया जो 09.11.2016 से प्रभावी हुआ।
- (iii). दरमानों के कार्यान्वयन के पश्चात्, चेन्नई पोर्ट स्टीवडोर एसोसिएशन (सीपीएसए) ने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और यह कहते हुए आधी-पाली गैंग की संकल्पना को पुनः लागू करने का अनुरोध किया कि आधी-पाली गैंग उन कुछेक पहल प्रयासों में से एक है जिसका स्टीवडोर समुदाय द्वारा तहे - दिल से स्वागत और प्रशंसा की गई थी। यह मानते हुए कि आधी-पाली गैंग व्यवस्था को पुनः लागू करने से पोत की टीआरटी में कमी आयेगी और पत्तन की कार्यक्षमता में सुधार होगा, आधी-पाली गैंग व्यवस्था को पुनः लागू करने के लिए बोर्ड की 23 मई, 2017 को हुई बैठक के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया था।

- (iv). सीएचपीटी के बोर्ड ने व्यापार सूचना जारी करते हुए 5 जून, 2017 से आने और कार्य समाप्त पोतों के लिए आधी-पाली गैंग सिस्टम पुनः लागू करने और दरमानों में आशोधन के लिए प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजने का संकल्प पारित किया। इस संबंध में 23 मई 2017 के बीआर संख्या 33 के बोर्ड संकल्प तथा यातायात प्रबंधक द्वारा जारी 03.06.2017 की व्यापार सूचना संख्या पी.11/070/2017/टी (पी) की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई हैं।

3.2. उपरोक्त को देखते हुए, सीएचपीटी ने आधी-पाली व्यवस्था को पुनः लागू करने के संबंध में सीएचपीटी के वर्तमान दरमानों के भाग-4 में अनुसूची 4.1 के नीचे वर्तमान टिप्पणी (1) के पश्चात् निम्नलिखित दो टिप्पणियां अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव किया है:

- "(2) स्टीवडोरों को समय-दर मज़दूरी का 50% और उपरोक्त अनुसूची के योग कॉलम में उल्लिखित सामान्य उगाही का 192% भुगतान करने पर आने वाले और कार्य समाप्त पोतों के लिए पूरी पाली के स्थान पर आधी-पाली के लिए गैंग की मांग करने की अनुमति दी जाती है।
- (3) जब कभी आधी-पाली गैंग की सेवाओं को पूरी पाली गैंग में परिवर्तित किया जायेगा, तो स्टीवडोर को निवारक उपाय के रूप में आधी पाली गैंग प्रभारों के अतिरिक्त एक पूर्ण गैंग प्रभार का भुगतान करना होगा।"

3.3. सीएचपीटी ने यह भी बताया है कि प्रस्तावित दरमानों पर, प्राधिकरण को दरमानों के सामान्य संशोधन के दौरान प्रस्तुत वार्षिक राजस्व अपेक्षा (ए.आर.आर.) 755.93 करोड़ रु. के प्रति 550.95 करोड़ रु. आकलित की गयी थी। इस प्रकार, आधी-पाली गैंग व्यवस्था को पुनः लागू करने पर दरमानों में और घटौती आयेगी और इसलिए, सामान्य संशोधन प्रस्ताव के अनुसार यह एआरआर के काफी भीतर ही है।

3.4. तदनुसार, सीएचपीटी ने इस प्राधिकरण को आधी-पाली गैंग व्यवस्था को 05 जून, 2017 से पुनः लागू करने के प्रस्ताव पर विचार करने और दरमानों में उपरोक्त संशोधन अनुमोदित करने का अनुरोध किया है।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, सीएचपीटी के 28 जुलाई, 2017 के प्रस्ताव को संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों से उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए उठाया गया। इस संबंध में, कुछेक प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों नामतः चेन्नई पोर्ट स्टीवडोर एसोसिएशन, साउदर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान चैम्बर्स ऑफ कामर्स और पैसिफिक साल्यूशनज प्रा. लि. के क्रमशः 21 अगस्त, 2017, 29 अगस्त, 2017 और 7 सितंबर, 2017 के ई-मेल द्वारा प्रस्ताव का स्वागत किया है और पत्तन के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है।

5.1. तत्पश्चात्, जैसा सीएचपीटी ने बांछा प्रकट की है, सीएचपीटी के प्रस्ताव की एक प्रति चेन्नई एंड एन्नोर पोर्ट स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन (सीएचईएनएसए) को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई।

5.2. सीएचईएनएसए की दिनांक 12 सितंबर, 2017 की टिप्पणियों को हमारे 14 सितंबर 2017 के समसंख्यक पत्र के द्वारा सीएचपीटी को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया। सीएचपीटी ने अपने 23 अक्टूबर, 2017 के पत्र के द्वारा प्रत्युत्तर दिया। सीएचईएनएसए से प्राप्त टिप्पणियों और उन पर सीएचपीटी की टिप्पणियों को नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:-

क्र.सं.	सीएचईएनएसए की टिप्पणियां	सीएचपीटी का उत्तर
	किन्हीं अप्रत्याशित स्थितियों/ परिचालन/ तकनीकी मुद्दों, यदि कोई हो, जो अंतिम क्षणों में उठ सकते हैं, को देखते हुए, जिनकी वजह से स्टीवडोर को आधी-पाली से पूरी-पाली गैंग में बदलने को मज़बूर कर सकते हैं को देखते हुए दांडिक खंड अर्थात् " यदि आधी-पाली गैंग की सेवाओं को पूरी पाली गैंग में परिवर्तित किया जाता है, तो स्टीवडोर को निवारक उपाय के रूप में आधी पाली गैंग प्रभारों के अतिरिक्त एक पूर्ण गैंग प्रभार का भुगतान करना होगा।"	आधी पाली गैंग व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य पत्तन के दक्षता प्रतिमानों में सुधार लाना है, अर्थात्, पोतों की टीआरटी को कम करना। चूंकि, कार्य समाप्त पोतों के लिए आधी -पाली गैंग स्टीवडोर नियोक्ताओं के लिए ऐच्छिक है और जब आधी-पाली गैंग को पूरी पाली गैंग में परिवर्तित किया जाता है, इससे न केवल कार्यकारी पोत की टीआरटी प्रभावित होगी, अपितु, प्रतीक्षारत पोतों की प्री-वर्थ डिटेंशन (पीबीडी) भी बढ़ जायेगी, जो वर्थ विशेष के लिये प्रतिक्षारत होते हैं। एक स्टीवडोर को, जो आधी-

<p>चूंकि स्टीवडोर को यदि अपेक्षित हुआ तो कार्गो परिचालन पूरा करने के लिए पहले ही आधी-पाली गैंग को पूरी पाली-गैंग में बदलने पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। पत्तन द्वारा दांडिक प्रभार आरोपित करने से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।</p>	<p>पाली गैंग को तैनात करता है को इतनी जानकारी तो होती ही है कि कार्यों में लगभग कितना समय लगने की संभावना है। यदि उसे आधी-पाली से पूरी पाली में परिवर्तन करना पड़ता है तो यह उसकी घटिया आयोजना और स्टीवडोर की कार्य निष्फलता को दर्शाता है। परिचालनात्मक तकनीकी कारणों से कार्गो परिचालनों का रोका जाना तो दूर की बात है। ऐसा अधिकतर स्टीवडोरों की अनुपयुक्त योजना के कारण ही होता है। यदि इस उपबंध को हटा दिया जाता है, तो स्टीवडोर अपने कार्यकलापों को सतर्कता से नियोजित नहीं करेंगे और इस प्रकार, पोत परिचालनों में विलंब होगा। इससे आधी-पाली गैंग व्यवस्था लागू करने का प्रयोजन ही विफल हो जायेगा।</p> <p>उक्त उपबंध स्टीवडोरों पर आधी-पाली के लिए योजना बनाते समय असावधानी बरतने से रोक के रूप में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, आधी-पाली लागू होने से पत्तन को भी वित्तीय हानि होती है। इसलिए, दांडिक उपबंध औचित्यपूर्ण है।</p>
---	---

6. मामले की प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के हवाले से निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है:—

- (i). चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) में कार्गो प्रहस्तन परिचालनों के लिए आधी-पाली गैंग प्रभारों की उगाही, जिसे इस प्राधिकरण के अनुमोदन से वर्ष 2014 में लागू किया गया था और इस प्राधिकरण के अनुमोदन से वर्ष 2016 में वापस ले लिया गया था, व्यापार द्वारा किये गए अनुरोध पर सीएचपीटी द्वारा अब फिर से लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार, पत्तन का संदर्भाधीन प्रस्ताव सीएचपीटी में आने वाले और कार्य समाप्त कर जाने वाले पोतों के संदर्भ में कार्गो प्रहस्तन परिचालनों के लिए पूरी पाली प्रभारों के स्थान पर आधी-पाली गैंग प्रभारों को लागू करने का है। सीएचपीटी के प्रस्ताव को न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है।
- (ii). प्रशुल्क नीति, 2015 का खंड 5.4 अनुबद्ध करता है कि यदि किसी प्रस्ताव अथवा मामले में प्रयोक्ताओं से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो प्राधिकरण को किसी संयुक्त सुनवाई को आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में प्रयोक्ता संगठनों ने प्रस्ताव का स्वागत किया है और आम तौर पर आधी-पाली गैंग व्यवस्था को पुनः लागू करने पर अपनी सहमति जताई है। अतः संदर्भाधीन मामले में किसी संयुक्त सुनवाई की जरूरत महसूस नहीं की गई।
- (iii). सीएचपीटी ने आधी-पाली गैंग व्यवस्था को इस आधार पर पुनः लागू करने का प्रस्ताव किया है कि आधी-पाली गैंग उन कुछेक पहल प्रयासों में से एक है जिसका स्टीवडोर समुदाय द्वारा तहे- दिल से स्वागत और प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त पत्तन की राय यह है कि आधी-पाली गैंग व्यवस्था के पुनः लागू होने से पोत के टर्न अराउंड समय (टीआरटी) में कमी आयेगी और पत्तन की कार्यक्षमता में सुधार होगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस प्राधिकरण द्वारा की गई परामर्शी प्रक्रिया में, सभी प्रयोक्ता संगठनों ने प्रस्ताव का स्वागत किया है और आधी-पाली गैंग व्यवस्था को पुनः लागू करने के लिए अपनी सहमति दी है।

इस संबंध में, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि यद्यपि पत्तन ने आधी-पाली गैंग व्यवस्था के पुनः लागू होने पर पत्तन के राजस्व में घटौती की पुष्टि की है, तथापि इसने व्यापार की मांग को स्वीकार करने में बड़ा सोच समझ कर निर्णय लिया है और आधी-पाली गैंग व्यवस्था लागू की गयी है।

- (iv). यह बताया गया है कि सीएचपीटी के प्रस्ताव को उसके न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है और चूंकि प्रयोक्ताओं ने सीएचपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित आधी-पाली गैंग व्यवस्था को पुनः लागू करने पर सहमति जताई है, यह प्राधिकरण सीएचपीटी के प्रस्ताव को अनुमोदन देने को प्रवृत्त है।
- (v). पत्तन द्वारा ऐसे किसी भी प्रभार की उगाही, को जो महापत्तन न्यास, 1963 की धारा 48 के अंतर्गत आते हैं, इस प्राधिकरण के अनुमोदन की अपेक्षा होती है। सीएचपीटी द्वारा किये गए निवेदन से यह पाया गया है कि सीएचपीटी ने न्यासी मंडल के अनुमोदन से 28 जुलाई, 2017 को अपने प्रस्ताव को दायर करने से काफी पहले 5 जून 2017 से व्यापार परिपत्र जारी कर आधी-पाली गैंग व्यवस्था लागू कर दी है। इस प्रकार सीएचपीटी ने इस प्राधिकरण को संपन्न कार्य की स्थिति में प्रस्ताव को 5 जून 2017 से संशोधन को अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। पत्तन ने प्रशुल्क के आशोधन की अग्रिम कार्रवाई करना अथवा इस प्राधिकरण के समक्ष संपन्न कार्य की स्थिति प्रस्तुत करने के स्थान पर नई दरें लागू करने की प्रत्याशा नहीं की जाती। कार्यकारी दिशानिर्देशों में किसी नई सुविधा अथवा नई सेवा के लिए दरों की अधिसूचना के साथ ही साथ प्रस्तावित दरों की तदर्थ आधार पर उगाही के लिए प्रस्ताव दायर करने का उपबंध किया गया है।
- (vi). आम तौर पर इस प्राधिकरण के आदेश राजपत्र की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होते हैं जब तक कि संबंधित प्रशुल्क आदेश में विशेष रूप से विभिन्न व्यवस्था का उल्लेख न किया गया हो। आपवादिक मामलों में, पूर्व-व्यापी प्रभाव भी दिया जाता है और उसके कारण दर्ज किये जाते हैं। संदर्भाधीन मामले में 05 जून 2017 से पूर्व व्यापी प्रभाव देने में प्रयोक्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए यह प्राधिकरण आधी-पाली गैंग प्रभारों की 05 जून, 2017 से उगाही करने के पूर्व-व्यापी प्रभाव का अनुमोदन करने को सहमत है। तथापि, सीएचपीटी को इस प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन करने से पूर्व दरमानों और स्थितियों में परिवर्तन की सूचना व्यापार परिपत्र जारी करके लागू न करने की सलाह दी जाती है।

7.1. परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण सीएचपीटी के वर्तमान दरमानों के भाग-4, अनुसूची 4.1 के नीचे आने और कार्य समाप्त कर जाने वाले पोतों के लिए आधी-पाली गैंग व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों को अंतर्विष्ट करने का अनुमोदन करता है:-

- “(2) स्टीवडोरों को समय-दर मज़दूरी का 50% और उपरोक्त अनुसूची के योग कालम में उल्लिखित सामान्य उगाही का 192% भुगतान करने पर आने वाले और कार्य समाप्त पोतों के लिए पूरी पाली के स्थान पर आधी-पाली के लिए गैंग की मांग करने की अनुमति दी जाती है।
- (3) जब कभी आधी-पाली गैंग की सेवाओं को पूरी पाली गैंग में परिवर्तित किया जाता है, तो स्टीवडोर को निवारक उपाय के रूप में आधी-पाली गैंग प्रभारों के अतिरिक्त एक पूर्ण गैंग प्रभार का भुगतान करना होगा।”

7.2 सीएचपीटी को उक्त उपबंधों को दरमानों में उपयुक्त रूप से शामिल करने का निदेश दिया जाता है।

7.3. उक्त उपबंध 05 जून, 2017 से प्रभावी समझे जाएंगे और इनकी वैधता सीएचपीटी के वर्तमान दरमानों की 31 मार्च, 2019 तक की वैधता के साथ सह-समाप्य रहेगी।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./317/17]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION**

Mumbai, the 21st November, 2017

**No. TAMP/65/2017-CHPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Chennai Port Trust for re-introduction of half shift gang system for cargo handling operations as a modification to its existing Scale of Rates approved vide Order No.TAMP/22/2016-CHPT dated 17 September 2016, as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports****Case No. TAMP/65/2017-CHPT****Chennai Port Trust**

-----

**Applicant****QUORUM:**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on this 14<sup>th</sup> day of November 2017)

This case relates to a proposal dated 28 July 2017 received from the Chennai Port Trust (CHPT) for re-introduction of half shift gang system for cargo handling operations as a modification to its existing Scale of Rates approved *vide* Order No.TAMP/22/2016-CHPT dated 17 September 2016.

2.1. In the year 2014, the CHPT had, *interalia*, proposed introduction of a note in the Scale of Rates relating to charges for supply of cargo handling working and supervisory staff to the effect that the Stevedores will be permitted to indent gang for half shift instead of full shift for incoming and finishing vessels on permanent basis, by making payment of 50% of existing wages and 192% levy on 50% wages. The said note was proposed to be introduced by the Port then, on the ground that the Stevedores are reluctant to engage gangs for part shift workings as they have to pay full gang charges and that prescription of half shift charges will induce Stevedores to indent labour for half-shifts, thereby leading to generation of additional income due to handling of more vessels. As recorded in the paragraph no. 12 (xiv) of the order dated 28 November 2014, the CHPT then reported that the introduction of Half Shift Gang system in consultation with the recognised Trade Unions and Stevedores Association has resulted in increase of ship day output, reduction of idle hours and turn around time of vessels. In the long run, it would generate additional income due to handling of more vessels. Accordingly, this Authority vide its Order No. TAMP/19/2014-CHPT dated 28 November 2014 has, *interalia*, approved introduction of the note proposed by CHPT then.

2.2. However, subsequently, in the proposal submitted by CHPT for general revision of Scale of Rates, the CHPT stated that implementation of NIT Award in September 2015 resulted in reduction of labour cost by around 16% and keeping the stevedoring labour charges and the percentage of General Levy intact, the CHPT had proposed to discontinue the half shift gang charges. There was no pointed objection from the users for discontinuance of half shift gang charges. This Authority in its Order No.TAMP/22/2016-CHPT dated 17 September 2016, while disposing of the general revision proposal filed by CHPT, accorded approval to the discontinuance of half shift gang charges.

3.1. In this backdrop, the CHPT vide its letter No. A.O(SoR)/10611/2015/FR dated 28 July 2017 has filed a proposal for re-introduction of half shift gang system, based on the representations received from Stevedores. The main points made by CHPT are summarized below:

- (i). The Scale of Rates of CHPT prescribes time-rate wages and general levy of 192% for deployment of labour for cargo handling operations on 'per shift' basis. Based on the representations from the Stevedores, the system of Half-shift Gang charges was introduced for incoming vessels in April 2013 and subsequently extended for finishing vessels also from June 2013 after obtaining Board's approval. Accordingly,

Stevedores were permitted to engage half-shift gangs on payment of 50% of the time rate wages and levy on arrival in respect of incoming vessels and at the time of sailing in respect of finishing vessels. Necessary provision in this regard was included in the Scale of Rates in Chapter-VII – Scale-1 – Stevedoring Operations under Note 2 (b), vide TAMP Order No.TAMP/19/2014-CHPT dated 28.11.2014, notified on 10.12.2014 vide G. No.358.

- (ii). At the time of general revision of Scale of Rates during 2016, the system of half-shift gang charges was dropped, taking into account the implementation of NIT Award leading to drastic reduction in the manning scale and the revenue loss to the Port due to under utilization of the workers posted for half-shift for the remaining period of the shift. The proposal of CHPT for revision of SoR was hosted in the Trust's website and a joint hearing was also held by TAMP on 21.7.2016. Thereafter, TAMP vide Order No.TAMP/22/2016-CHPT dated 17.9.2016 approved the revised Scale of Rates of CHPT which came into effect from 09.11.2016.
- (iii). After implementation of the Scale of Rates, Chennai Port Stevedores Association (CPSA) requested to reconsider the decision and reinstate the concept of half-shift gang stating that the half-shift gang is one of the few initiatives that was wholeheartedly welcomed and appreciated by the stevedoring community. Also recognizing that re-introduction of half-Shift Gang System would contribute to reduction in TRT of the vessel and improve port efficiency, a proposal was placed before the Board in its meeting held on 23<sup>rd</sup> May 2017 to re-introduce the Half-Shift Gang system.
- (iv). The Board of CHPT has resolved to approve re-introduction of half-shift gang system for incoming and finishing vessels with effect from 5<sup>th</sup> June 2017 by issuing a Trade Notice and submit the proposal to TAMP for modification of the Scale of Rates. A copy each of the Board Resolution in this regard vide B.R. No.33 dated 23.5.2017 and Trade notice issued by the Traffic Manager vide P11/070/2017/T(P) dated 3.06.2017 have been furnished.

3.2. In view of the above, the CHPT has proposed to insert the following two notes after existing Note (1) under Schedule 4.1, Section-4 of the existing Scale of Rates of CHPT in connection with the re-introduction of half-shift gang system:

- “(2) The stevedore will be permitted to indent gang for half shift instead of full shift for incoming and finishing vessels, by making payment of 50% of time-rate wages and 192% general levy mentioned in the Total column of the above schedule.
- (3) Whenever the services of half shift gang is converting into full shift gang, the Stevedores shall pay one full gang charges over and above the half shift gang charges as a deterrent measure.”

3.3. The CHPT has also stated that the revenue at the proposed Scale of Rates was estimated at ₹ 550.95 crores as against the Annual Revenue Requirement (ARR) of ₹ 755.93 crores submitted during the general revision of SOR to TAMP. As such, proposed modification in the Scale of Rates to re-introduce half shift gang systems will result in further reduction of revenue to the Port and will, therefore, be well within the ARR as per the General Revision proposal.

3.4. Accordingly, the CHPT has requested this Authority to consider the proposal of the CHPT to re-introduce half shift gang with effect from 5 June 2017 and accord its approval for the above modifications in the Scale of Rates.

4. In accordance with the consultative procedure prescribed, the CHPT proposal dated 28 July 2017 was taken up on consultation with concerned users/ user organisations seeking their comments. In this connection, some of users/ user organisations viz., Chennai Port Stevedores Association, Southern India Chamber of Commerce & Industry, Hindustan Chamber of Commerce and Indo-Pacific Solution Pvt. Ltd. vide their e-mails dated 21 August 2017, 23 August 2017, 29 August 2017 and 07 September 2017 respectively have welcomed the proposal and have given their consent to the proposal of the Port.

5.1. Subsequently, as desired by CHPT, a copy of the CHPT proposal was forwarded to Chennai and Ennore Port Steamer Agent's Association (CHENSAA), for its comments.

5.2. The comments of CHENSAA dated 12 September 2017 was forwarded to CHPT for its comments *vide* our letter of even number dated 14 September 2017. The CHPT has responded *vide* its letter dated 23 October 2017. The comments received from the CHENSAA and comments of CHPT thereon are tabulated below:

Sl. No.	Comments of the CHENSAA	Reply furnished by CHPT
	<p>It is requested to consider waiving the penal clause i.e. "in the event half shift gang is converted into full shift gang the stevedores shall pay one full gang charge over and above the half shift gang charges as deterrent measure", taking into account any unforeseen circumstances/ operational technical issues, if any that may arise, at last moment which may cause / push the Stevedores to convert half shift gang into full shift gang.</p> <p>Since stevedores will again be incurring additional cost by extending the half shift gang to full shift gang, if required, to complete the cargo operation, further imposing penal charges by the Port will lead to huge losses to us.</p>	<p>The purpose of introduction of half shift gang system is to improve the port efficiency parameters viz., reduce the TRT of vessels. As engaging of half shift gang for finishing vessels is optional on the part of the Stevedores employers and when half shift gang is converted as a full shift gang, it will not only affect the TRT of the working vessel, but also increase the Pre Berthing Detention (PBD) of the waiting vessels which may wait for a specific berth. A Stevedore engaging a half shift gang should be well aware of the approximate time required to complete the cargo handling activities. If it requires extension of half shift to full shift, it shows the poor planning and inefficiency on the part of the Stevedore. Holding up of cargo operations due to operational technical issues is only remote and mostly only on account of inappropriate planning by Stevedores.</p> <p>If the provision is removed the stevedore may not plan their activities meticulously thus resulting in delay in vessel operation which will defeat the very purpose of introduction of half shift gang system.</p> <p>The said clause is included as a deterrent to prevent stevedore from acting in a casual manner while planning for a half shift. Further introduction of half shift results in financial loss to the Port also. Therefore, the penal provision is well justified.</p>

6. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The levy of half shift gang charges for cargo handling operations at Chennai Port Trust (CHPT) which was introduced in the year 2014 by CHPT with the approval of this Authority and withdrawn in the year 2016 with the approval of this Authority, is now being proposed to be reintroduced by the CHPT, based on the request reported to have been made by the Trade. Thus, the proposal of the port under reference is to reintroduce half shift gang charges instead of full shift charges for cargo handling operations in respect of incoming and finishing vessels at CHPT. The proposal of the CHPT has the approval of its Board of Trustees.



- (ii). Clause 5.4 of the Tariff Policy, 2015, stipulates that in case there are no objections from users for a proposal or a case, this Authority need not organize any joint hearing. Given that in the instant case, the user organisations have generally welcomed the proposal for re-introduction of half shift gang system, no joint hearing was felt necessary in the case in reference.
- (iii). The reintroduction of half shift gang system has been proposed by the CHPT on the ground that half-shift gang is one of the few initiatives that has been wholeheartedly welcomed and appreciated by the stevedoring community. Further, the port is of the view that re-introduction of half-Shift Gang System would contribute to reduction in Turnaround Time (TRT) of Vessel and improve port efficiency. As brought out above, in the consultation process carried out by this Authority, all the user organisations have welcomed the proposal and have given their consent for re-introduction of half shift gang system.

In this regard, it is relevant to mention here that though the Port has confirmed about reduction in the revenue to the Port on account of re-introduction of half shift gang system, it has consciously taken a decision to accede to the demand of the trade and introduce the half shift gang system.

- (iv). Given that the proposal of the CHPT has the approval of its Board of Trustees and since the users have given consent to the re-introduction of half shift gang system as proposed by the CHPT, this Authority is inclined to accord approval to the proposal of the CHPT.
- (v). Levy of any charges by the Port which are covered by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, requires approval of this Authority. From the submissions made by CHPT, it is noticed that the CHPT, with the approval of its Board of Trustees, has already introduced the half shift gang system with effect from 5 June 2017 by way of issue of a Trade Circular much prior to filing its proposal on 28 July 2017. Thus, the CHPT has sought approval to the proposed amendment with effect from 5 June 2017 presenting a fait accompli situation to this Authority. It may not be unreasonable to expect a port to take advance action for modification of tariff or introduction of any new rates instead of presenting fait accompli situation before this Authority. The working guidelines provide for filing of the proposal for notification of rate for use of a new facility or a new service and levy of proposed rates on adhoc manner simultaneously.
- (vi). Orders of this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. In exceptional cases, retrospective effect is given for reason to be recorded. In the case in reference, there is no objection from the users with regard to retrospective effect from 05 June 2017. In view of this position, this Authority is inclined to grant approval for retrospective levy of half shift gang charges with effect from 05 June 2017. However, the CHPT is advised to refrain from issuing Circulars to Trade intimating about change in the Scale of Rates and conditions, prior to this Authority according approval to the proposed changes.

7.1. In the result, and for the reasons given above, and based on the collective application of mind, this Authority approves to insert the following notes relating to half-shift gang system for incoming and finishing vessels under Schedule 4.1, Section-4 of the existing Scale of Rates of CHPT:

- “(2) The stevedore will be permitted to indent gang for half shift instead of full shift for incoming and finishing vessels, by making payment of 50% of time-rate wages and 192% general levy mentioned in the Total column of the above schedule.
- (3) Whenever the services of half shift gang is converting into full shift gang, the Stevedores shall pay one full gang charges over and above the half shift gang charges as a deterrent measure.”

7.2 The CHPT is directed to suitably incorporate the above provisions in its Scale of Rates.

7.3. The abovesaid provisions are deemed to have come into effect from 5 June 2017 and its validity will remain co-terminus to the validity of the existing Scale of Rates of CHPT upto 31 March 2019.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./317/17]